

इको सेंसिटिवि ज़ोन पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

प्रलिस के लयि:

इको सेंसिटिवि ज़ोन, पर्यावरण (संरक्षण) अधनियम, 1986, राष्ट्रिय वन्यजीव कार्ययोजना, राष्ट्रिय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षति वन ।

मेन्स के लयि:

जेवविधिता और इसका संरक्षण, इको सेंसिटिवि ज़ोन, पर्यावरण (संरक्षण) अधनियम, 1986, राष्ट्रिय वन्यजीव कार्ययोजना ।

चर्चा में क्यो?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने नरिदेश दया क देश भर में प्रत्येक संरक्षति वन, राष्ट्रिय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में उनकी सीमांकति सीमाओं से कम-से-कम एक कमी. का अनवार्य **इको सेंसिटिवि ज़ोन (ESZ)** होना चाहयि ।

- यह फैसला तमलिनाडु के नीलगरि ज़िलि में वन भूमिकी सुरक्षा के लयि दायर एक याचकिका पर आया है ।

फैसले की मुख्य वशेषताएँ:

- केंद्र ने फरवरी 2011 में ESZ पर दशा-नरिदेश जारी करते हुए राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों से प्राप्त प्रतिकरियाओं के आधार पर **10 कलिमीटर की सीमा नरिधारति** की थी ।
 - न्यायालय इस तथ्य से अवगत था क सभी राष्ट्रिय उद्यानों और अभयारण्यों के लयि **एक समान ESZ संभव नहीं** होगा क्योक इसने **मुंबई में संजय गांधी राष्ट्रिय उद्यान और चेन्नई में गंडी राष्ट्रिय उद्यान** जैसे वशेष मामलों का उल्लेख कया जो महानगर के बहुत करीब स्थति हैं ।
- यद भौजूदा ESZ **1 कमी. बफर ज़ोन से अधिक होता है या यद कोई वैधानिक संस्था उच्च सीमा नरिधारति** कराती है, तो ऐसी वस्तारति सीमा मान्य होगी ।
- राष्ट्रिय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर खनन की अनुमति नहीं होगी ।
- नरिणय ऐसे सभी राज्यों/केंद्रशासति प्रदेशों में लागू होगा जहाँ न्यूनतम ESZ सीमा नरिधारति नहीं है ।
- व्यापक जनहति में ESZ की न्यूनतम चौड़ाई को कम कया जा सकता है ।
 - संबंधति राज्य या केंद्रशासति प्रदेश न्यायालय द्वारा नयुक्त **केंद्रीय अधिकार प्राप्त समति (CEC)** और **MOEFCC (पर्यावरण वन और जलवायु परविरतन मंत्रालय)** से संपर्क करेंगे और ये दोनों नकिया इस न्यायालय को संबंधति राय या सफिराशें देंगे जसिके आधार पर न्यायालय उचति आदेश पारति करेगा ।
- न्यायालय ने प्रत्येक राज्य और केंद्रशासति प्रदेश के **प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF)** को नरिदेश दया कविह प्रत्येक राष्ट्रिय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य के ESZ में जारी गतिविधियों की सूची प्रदान करते हुए न्यायालय को तीन महीने में रपौरट प्रस्तुत करे ।
- न्यायालय ने मामले को PCCF को यह सुनश्चिति करने के लयि सौंपा क ESZ के भीतर कोई नया स्थायी ढाँचा नहीं बने और जो पहले से ही कोई गतिविधिकर रहे हैं उन्हें छह महीने के भीतर PCCF से अनुमति हेतु नए सरि से आवेदन करना होगा ।

इको सेंसिटिवि ज़ोन:

- **परचय:**
 - पर्यावरण, वन और जलवायु परविरतन मंत्रालय (MoEFCC) की राष्ट्रिय वन्यजीव कार्ययोजना (2002-2016) ने नरिधारति कया क पर्यावरण संरक्षण अधनियम, 1986 के तहत राज्य सरकारों को राष्ट्रिय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 कमी. के भीतर आने वाली भूमिको इको सेंसिटिवि ज़ोन या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्तर (ESZ) घोषति करना चाहयि ।
- **उद्देशय:**
 - इसका मूल उद्देशय राष्ट्रिय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आस-पास कुछ गतिविधियों को वनियमति करना है ताक संरक्षति क्षेत्तरों के नकिटवर्ती संवेदनशील पारस्थतिकि तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव को कम कया जा सके ।

- ये क्षेत्र उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करेंगे।
- **नषिद्ध गतिविधियाँ:**
 - वाणज्यिक खनन, आरा मलिन, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, प्रमुख जलवदियुत परियोजनाओं की स्थापना, लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग।
 - पर्यटन गतिविधियाँ जैसे- राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर गर्म हवा के गुब्बारे, अपशष्टों का नरिवहन या कोई ठोस अपशष्ट या खतरनाक पदार्थों का उत्पादन।
- **वनियमि गतिविधियाँ:**
 - पेड़ों की कटाई, होटलों और रसोर्ट्स की स्थापना, प्राकृतिक जल का व्यावसायिक उपयोग, बजिली के तारों का नरिमाण, कृषिप्रणाली में भारी परिवर्तन, जैसे- भारी प्रोद्योगिकी, कीटनाशकों आदिको अपनाना, सड़कों को चौड़ा करना।
- **अनुमतप्राप्त गतिविधियाँ:**
 - संचालित कृषि या बागवानी प्रथाएँ, वर्षा जल संचयन, जैविक खेती, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, सभी गतिविधियों के लिये हरति प्रोद्योगिकी को अपनाना।
- **महत्त्व:**
 - **विकास गतिविधियों के प्रभाव को कम करना:**
 - शहरीकरण और अन्य विकासात्मक गतिविधियों के प्रभाव को कम करने के लिये संरक्षित क्षेत्रों से सटे क्षेत्रों को इको-सेसटिवि ज़ोन घोषित किया गया है।
 - **इन-सीटू संरक्षण:**
 - ESZ इन-सीटू संरक्षण में मदद करते हैं, जो अपने प्राकृतिक आवास में लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है, उदाहरण के लिये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण।
 - **वन क्षरण और मानव-पशु संघर्ष को कम करना:**
 - इको-सेसटिवि ज़ोन वनों की कमी और मानव-पशु संघर्ष को कम करते हैं।
 - संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन के मूल और बफर मॉडल पर आधारित होते हैं, जनिके माध्यम से स्थानीय क्षेत्र के समुदायों को भी संरक्षित और लाभान्वित किया जाता है।

इको-सेसटिवि ज़ोन के लिये चुनौतियाँ:

- **विकासात्मक गतिविधियाँ:**
 - ESZ में बाँधों, सड़कों, शहरी और ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के नरिमाण जैसी गतिविधियाँ हस्तक्षेप करती हैं, जो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं और पारस्थितिक तंत्र को असंतुलित करती हैं।
- **शासन और नए कानून:**
 - पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन समुदायों के अधिकारों की अनदेखी करते हैं तथा जानवरों के अवैध शिकार को रोकने में वफिल रहे हैं। ये ESZs में विकास गतिविधियों का समर्थन करते हैं।
- **पर्यटन:**
 - पर्यावरण पर्यटन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये वनों की कटाई, स्थानीय लोगों के वसिथापन आदिके माध्यम से पार्कों और अभयारण्यों के आसपास की भूमि को साफ किया जा रहा है।
- **वदेशी प्रजातियों का हस्तक्षेप:**
 - यूकेलपिटस और बबूल औरकियुलरसि आदि जैसी वदेशी प्रजातियाँ तथा उनका वृक्षारोपण प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वनों पर एक प्रतस्पर्धी दबाव पैदा करते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन:**
 - जलवायु परिवर्तन ने ESZs पर भूमि, जल और पारस्थितिक तनाव उत्पन्न किया है। उदाहरण के लिए बार-बार जंगल में आग या असम की बाढ़ जसिने **काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान** तथा उसके वन्यजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है।
- **स्थानीय समुदाय:**
 - झूम खेती, बढ़ती आबादी का दबाव और जलाऊ लकड़ी तथा वनोपज की बढ़ती मांग आदि संरक्षित क्षेत्रों पर दबाव डालते हैं।

आगे की राह

- राज्यों को प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में आम जनता के लाभ के लिये एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करना चाहिये ताकि दीर्घकालिक विकास किया जा सके।
- सरकार को अपनी भूमिका को राज्य के तत्काल उत्थान के लिये आर्थिक गतिविधियों के सूत्रधार की भूमिका तक सीमित नहीं रखना चाहिये।
- वनीकरण और अवक्रमित वनों का पुनर्वनीकरण, खोए हुए आवासों का पुनर्जनन, कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- संरक्षण तकनीकों का प्रचार-प्रसार करना और संसाधनों के अत्यधिक दोहन व जनता के बीच इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न. भारत में संरक्षित क्षेत्रों की नमिनलखिति में से कसि एक श्रेणी में स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है? (2012)

- (a) बायोस्फीयर रज़िर्व
- (b) राष्ट्रीय उद्यान
- (c) रामसर कन्वेंशन के तहत घोषित आर्द्रभूमि
- (d) वन्यजीव अभयारण्य

उत्तर: B

व्याख्या:

- **राष्ट्रीय उद्यान:** यह एक ऐसा क्षेत्र है जो अभयारण्य के भीतर स्थित हो या नहीं, राज्य सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठन के लिये अधिसूचित किया जा सकता है, इसका उद्देश्य पारिस्थितिक, जीव, पुष्प, भू-आकृत विज्ञान या प्राणी संघ या महत्त्व को देखते हुए आवश्यक वन्यजीवों या उसके पर्यावरण की रक्षा तथा उनका विकास करना है। राष्ट्रीय उद्यान के भीतर राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा अध्याय IV, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में उल्लिखित शर्तों के तहत प्रदान की गई अनुमति के सवाय, किसी भी प्रकार के मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं है।
- **बायोस्फीयर रज़िर्व:** ये जैवविविधता के बड़े-बड़े क्षेत्र हैं जहाँ वनस्पतियों और जीवों की रक्षा की जाती है। पर्यावरण संरक्षण के ये क्षेत्र मोटे तौर पर IUCN श्रेणी V संरक्षित क्षेत्रों के अनुरूप हैं। भारत के बायोस्फीयर रज़िर्व में प्रायः एक या एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य शामिल होते हैं, साथ ही बफर जोन भी होते हैं जो **कृषि आर्थिक गतिविधियों के लिये खुले** होते हैं। यह संरक्षण न केवल संरक्षित क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों को प्रदान किया जाता है, बल्कि उन मानव समुदायों को भी प्रदान किया जाता है जो इन क्षेत्रों में रहते हैं।
- **वन्यजीव अभयारण्य:** इसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से परभाषित किया गया है। वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के लिये राज्य विधानसभा द्वारा कानून पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। राज्य विधायिका संकल्प के माध्यम से सीमा का निर्धारण और प्रत्यावर्तन कर सकती है। **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL)** की मंजूरी के बिना वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। अभयारण्य में **सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति है।**
- **रामसर कन्वेंशन के तहत अनुसूचित आर्द्रभूमि के स्थानीय लोगों को आर्द्रभूमि से बायोमास इकट्ठा करने से नहीं रोका जाता है बल्कि वे स्थानीय लोगों को आर्द्रभूमि के संरक्षण में भागीदार बनाते हैं। अतः विकल्प B सही है।**

स्रोत: द हिंदू

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sc-judgement-on-eco-sensitive-zone>

